e-ISSN: 2319-8753 | p-ISSN: 2347-6710

IJIRSET
International Journal of Innovative Research in
SCIENCE | ENGINEERING | TECHNOLOGY

# INTERNATIONAL JOURNAL OF INNOVATIVE RESEARCH

IN SCIENCE | ENGINEERING | TECHNOLOGY

Volume 10, Issue 12, December 2021

INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER INDIA

Impact Factor: 7.569

| e-ISSN: 2319-8753, p-ISSN: 2347-6710| www.ijirset.com | Impact Factor: 7.569|

|| Volume 10, Issue 12, December 2021 ||

| DOI:10.15680/IJIRSET.2021.1012175 |

# भारत-अमेरिका संबंध: वर्तमान परिप्रेक्ष्य

**Dr. Dhiraj Bakolia**

Associate Professor, Dept. of Political Science, Govt. Lohia College, Churu (Rajasthan), India

### सार

अमेरिका-भारत साझेदारी स्वतंत्रता, लोकतांत्रिक सिद्धांतों, सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार, मानवाधिकारों और कानून के शासन के प्रति साझा प्रतिबद्धता पर आधारित है। संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के व्यापार, निवेश और कनेक्टिविटी के माध्यम से वैश्विक सुरक्षा, स्थिरता और आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देने में साझा हित हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका यह सुनिश्चित करने के प्रयासों में एक प्रमुख वैश्विक शक्ति और महत्वपूर्ण भागीदार के रूप में भारत के उदय का समर्थन करता है कि इंडो-पैसिफिक शांति, स्थिरता और बढ़ती समृद्धि का क्षेत्र है। हमारे देशों के बीच मजबूत जन दर जन संबंध, जो चार मिलियन भारतीय-अमेरिकी प्रवासी में परिलक्षित होता है, साझेदारी के लिए ताकत का एक जबरदस्त स्रोत है। दिसंबर 2019 में, संयुक्त राज्य अमेरिका ने अमेरिकी विदेश और रक्षा सचिवों और उनके भारतीय समकक्षों के नेतृत्व में वाशिंगटन में दूसरी 2 + 2 मंत्रिस्तरीय वार्ता की मेजबानी की,जिस पर दोनों पक्षों ने एक प्रमुख रक्षा भागीदार के रूप में भारत की स्थिति की पुष्टि की और समुद्री सुरक्षा, अंतरसंचालनीयता और सूचना साझा करने पर सहयोग को गहरा किया। जबकि 2+2 संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के बीच प्रमुख संवाद तंत्र के रूप में कार्य करता है, तीस से अधिक द्विपक्षीय संवाद और कार्य समूह हैं, जो अंतरिक्ष और स्वास्थ्य सहयोग से लेकर ऊर्जा और उच्च प्रौद्योगिकी व्यापार तक मानव प्रयास के सभी पहलुओं को फैलाते हैं। इनमें यूएस-इंडिया काउंटर टेररिज्म ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप शामिल है, जिसे 2000 में स्थापित किया गया था और यह हमारी सबसे पुरानी सरकार से सरकारी संवादों में से एक है, साथ ही रणनीतिक ऊर्जा साझेदारी, साइबर डायलॉग, सिविल स्पेस वर्किंग ग्रुप, ट्रेड पॉलिसी फोरम, डिफेंस पॉलिसी ग्रुप और बहुत अधिक।इंटरऑपरेबिलिटी, और सूचना साझाकरण। जबकि 2+2 संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के बीच प्रमुख संवाद तंत्र के रूप में कार्य करता है, तीस से अधिक द्विपक्षीय संवाद और कार्य समूह हैं, जो अंतरिक्ष और स्वास्थ्य सहयोग से लेकर ऊर्जा और उच्च प्रौद्योगिकी व्यापार तक मानव प्रयास के सभी पहलुओं को फैलाते हैं। इनमें यूएस-इंडिया काउंटर टेररिज्म ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप शामिल है, जिसे 2000 में स्थापित किया गया था और यह हमारी सबसे पुरानी सरकार से सरकारी संवादों में से एक है, साथ ही रणनीतिक ऊर्जा साझेदारी, साइबर डायलॉग, सिविल स्पेस वर्किंग ग्रुप, ट्रेड पॉलिसी फोरम, डिफेंस पॉलिसी ग्रुप और बहुत अधिक।इंटरऑपरेबिलिटी, और सूचना साझाकरण। जबकि 2+2 संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के बीच प्रमुख संवाद तंत्र के रूप में कार्य करता है, तीस से अधिक द्विपक्षीय संवाद और कार्य समूह हैं, जो अंतरिक्ष और स्वास्थ्य सहयोग से लेकर ऊर्जा और उच्च प्रौद्योगिकी व्यापार तक मानव प्रयास के सभी पहलुओं को फैलाते हैं। इनमें यूएस-इंडिया काउंटर टेररिज्म ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप शामिल है, जिसे 2000 में स्थापित किया गया था और यह हमारी सबसे पुरानी सरकार से सरकारी संवादों में से एक है, साथ ही रणनीतिक ऊर्जा साझेदारी, साइबर डायलॉग, सिविल स्पेस वर्किंग ग्रुप, ट्रेड पॉलिसी फोरम, डिफेंस पॉलिसी ग्रुप और बहुत अधिक।अंतरिक्ष और स्वास्थ्य सहयोग से लेकर ऊर्जा और उच्च प्रौद्योगिकी व्यापार तक। इनमें यूएस-इंडिया काउंटर टेररिज्म ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप शामिल है, जिसे 2000 में स्थापित किया गया था और यह हमारी सबसे पुरानी सरकार से सरकारी संवादों में से एक है, साथ ही रणनीतिक ऊर्जा साझेदारी, साइबर डायलॉग, सिविल स्पेस वर्किंग ग्रुप, ट्रेड पॉलिसी फोरम, डिफेंस पॉलिसी ग्रुप और बहुत अधिक।अंतरिक्ष और स्वास्थ्य सहयोग से लेकर ऊर्जा और उच्च प्रौद्योगिकी व्यापार तक। इनमें यूएस-इंडिया काउंटर टेररिज्म ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप शामिल है, जिसे 2000 में स्थापित किया गया था और यह हमारी सबसे पुरानी सरकार से सरकारी संवादों में से एक है, साथ ही रणनीतिक ऊर्जा साझेदारी, साइबर डायलॉग, सिविल स्पेस वर्किंग ग्रुप, ट्रेड पॉलिसी फोरम, डिफेंस पॉलिसी ग्रुप और बहुत अधिक।

### परिचय

ट्रम्प प्रशासन भारत की तरजीही व्यापार स्थिति को समाप्त कर देता है, जो 1970 के दशक के एक कार्यक्रम का हिस्सा है जो विकासशील देशों के उत्पादों को अमेरिकी बाजार में शुल्क मुक्त प्रवेश करने की अनुमति देता है। ट्रंप का कहना है कि भारत ने अपने खुद के बाजार को " समान और उचित पहुंच " प्रदान नहीं की है। सप्ताह बाद, भारत ने 2018 में लगाए गए स्टील और एल्यूमीनियम पर अमेरिकी कर्तव्यों के जवाब में अट्ठाईस अमेरिकी उत्पादों पर टैरिफ थप्पड़ मारा। नई दिल्ली ने पहले प्रतिशोधी टैरिफ का मसौदा तैयार किया था, लेकिन व्यापार वार्ता के बीच उन्हें लागू करने पर रोक लगा दी थी।[1,2]

एक लाख से अधिक दर्शकों के साथ अहमदाबाद की रैली में, राष्ट्रपति ट्रम्प ने अमेरिका-भारत संबंधों और प्रधान मंत्री मोदी के नेतृत्व की प्रशंसा की। दोनों नेताओं ने नशीली दवाओं और मानसिक स्वास्थ्य पर एक साथ काम करने की योजना की घोषणा की । भारत अमेरिकी सैन्य उपकरणों में $ 3 बिलियन खरीदने के लिए सहमत है, और यूएस-आधारित तेल कंपनी एक्सॉनमोबिल ने राज्य

| e-ISSN: 2319-8753, p-ISSN: 2347-6710| www.ijirset.com | Impact Factor: 7.569|

|| Volume 10, Issue 12, December 2021 ||

| DOI:10.15680/IJIRSET.2021.1012175 |

के स्वामित्व वाली इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के साथ एक समझौते की घोषणा की। व्यापार के मुद्दों को हल करने के उद्देश्य से वर्षों की बातचीत के बावजूद , अधिकारी एक समझौते पर नहीं पहुंचते हैं, कृषि उत्पादों, टैरिफ और अन्य क्षेत्रों पर विभाजन शेष है। ट्रंप के दौरे के बीच, जानलेवा झड़पेंनई दिल्ली में एक विवादास्पद नागरिकता कानून से जुड़े हिंदुओं और मुसलमानों के बीच। ट्रम्प सार्वजनिक रूप से हिंसा का उल्लेख नहीं करते हैं या कानून पर कड़ा रुख नहीं अपनाते हैं, जो आलोचकों का कहना है कि मुसलमानों के साथ भेदभाव करता है।[3,4]

अमेरिका और भारतीय रक्षा और विदेशी मामलों के शीर्ष अधिकारियों ने अपने टू-प्लस-टू वार्ता के तीसरे दौर के दौरान एक खुफिया-साझाकरण समझौते पर हस्ताक्षर किए । बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट (बीईसीए) पिछले दो दशकों में दोनों देशों द्वारा हस्ताक्षरित चार मूलभूत सैन्य समझौतों में से अंतिम है । यह भारतीय ड्रोन और क्रूज मिसाइलों की सटीकता को बढ़ावा देने के लिए संवेदनशील भू-स्थानिक डेटा साझा करने की अनुमति देता है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, अमेरिकी रक्षा सचिव मार्क टी. एस्पर ने इंडो-पैसिफिक को मुक्त और खुला रखने के लिए देशों की प्रतिबद्धता पर जोर दिया, "विशेषकर चीन द्वारा बढ़ती आक्रामकता और अस्थिर गतिविधियों के आलोक में।[5,6]

## विचार – विमर्श

भारत-अमेरिका संबंधों में विचलन

व्यापार सौदा: व्यापार भारत और अमेरिका के बीच विवाद का एक प्रमुख कारण रहा है। भारत को अमेरिका द्वारा "टैरिफ किंग" के रूप में संदर्भित किया गया है जो "अत्यधिक उच्च" आयात शुल्क लगाता है । डोनाल्ड ट्रंप ने तैयार की अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी , आर्थिक आयाम पर इसका मतलब भारत समेत प्रमुख व्यापारिक साझेदारों के साथ अमेरिका के व्यापार घाटे को कम करना है। इसके अनुसरण में:

जून 2019 में, ट्रम्प प्रशासन ने सामान्यीकृत सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस (जीएसपी) योजना के तहत भारत के लाभों को समाप्त करने का निर्णय लिया , जो इस देश से अमेरिका को निर्यात किए गए $ 6 बिलियन से अधिक मूल्य के उत्पादों के लिए तरजीही, शुल्क-मुक्त पहुंच प्रदान करता है।[7,8]

| e-ISSN: 2319-8753, p-ISSN: 2347-6710| www.ijirset.com | Impact Factor: 7.569|

|| Volume 10, Issue 12, December 2021 ||

| DOI:10.15680/IJIRSET.2021.1012175 |

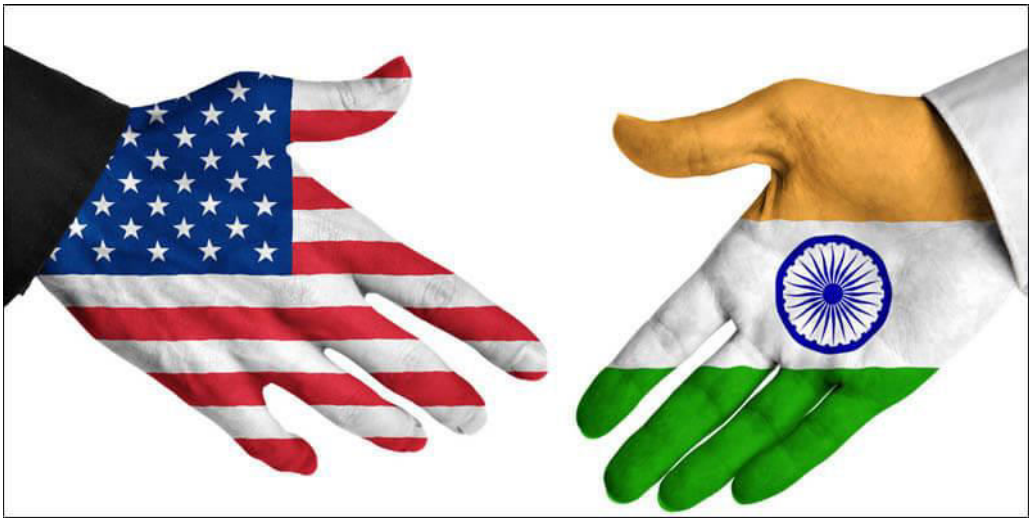

बढ़ते व्यापार तनाव के बीच जीएसपी सूची से हटाने से भारत को अंततः कई अमेरिकी आयातों पर प्रतिशोधात्मक शुल्क लगाने के लिए प्रेरित किया। इसने अमेरिका को भारत के खिलाफ विश्व व्यापार संगठन का रुख करने के लिए मजबूर कर दिया।

यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव (यूएसटीआर) के कार्यालय ने डिजिटल व्यापार के लिए "कुंजी" बाधा के रूप में कंपनियों को अपने नागरिकों के व्यक्तिगत डेटा को देश के बाहर भेजने से प्रतिबंधित करने के लिए भारत के उपायों को रेखांकित किया है।[9,10]

इसके अलावा, अमेरिका लंबे समय से अमेरिकी कृषि और डेयरी उत्पादों तक अधिक पहुंच की मांग करता रहा है। भारत के लिए, अपने घरेलू कृषि और डेयरी हितों की रक्षा करना RCEP समझौते से बाहर निकलने का एक प्रमुख कारण था ।

यूएस-पाकिस्तान समीकरण: अमेरिका ने पिछले सात महीनों में पाकिस्तान पर अपनी स्थिति को नरम कर दिया है, क्योंकि 29 फरवरी, 2020 को हस्ताक्षर किए जाने की संभावना वाले अफगान सौदे (अमेरिका और तालिबान के बीच) में पाकिस्तान की भूमिका हो सकती है।

बदले में, पाकिस्तान चाहता है कि अमेरिका कश्मीर मुद्दे पर भारत के साथ बातचीत करे ( कश्मीर मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण)। जबकि भारत का मानना है कि कश्मीर भारत और पाकिस्तान के बीच एक द्विपक्षीय मुद्दा है और इसमें किसी तीसरे पक्ष को शामिल नहीं किया जा सकता है।[11,12]

भारत में आंतरिक मुद्दे: भारत-अमेरिका मजबूत रणनीतिक साझेदारी भी लोकतंत्र के "साझा मूल्यों", कानून के शासन, धार्मिक स्वतंत्रता और अल्पसंख्यकों के संरक्षण के विचार पर आधारित है । हालाँकि, अनुच्छेद 370 का निरसन, नया नागरिकता कानून और NRC इस "साझा मूल्य" सिद्धांत का परीक्षण कर रहा है।

हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि ये मामले भारत के आंतरिक हैं, अमेरिकी कांग्रेस और अमेरिकी नागरिक समाज के कुछ हिस्सों की आलोचना अमेरिकी प्रशासन पर जोर दे रही है कि भारत को कश्मीर को सामान्य स्थिति में लाने के लिए कहें और नए नागरिकता कानून के साथ आगे न बढ़ें। एनआरसी।

भारत-अमेरिका संबंधों में अभिसरण

शीत युद्ध के बाद के युग में, रक्षा और रणनीतिक मुद्दों पर अमेरिका के साथ भारत के संबंध मजबूत हुए हैं। यह निम्नलिखित में परिलक्षित हो सकता है:

एक आधारभूत सैन्य समझौता जो एन्क्रिप्टेड संचार और उपकरण (COMCASA- संचार संगतता और सुरक्षा समझौता) को साझा करने की अनुमति देता है ।[13,14]

अमेरिकी निर्यात नियंत्रण कानूनों में बदलाव जो भारत को नाटो और गैर-नाटो अमेरिकी सहयोगियों की एक विशेषाधिकार प्राप्त श्रेणी में रखता है।

| e-ISSN: 2319-8753, p-ISSN: 2347-6710| www.ijirset.com | Impact Factor: 7.569|

|| Volume 10, Issue 12, December 2021 ||

| DOI:10.15680/IJIRSET.2021.1012175 |

एक औद्योगिक सुरक्षा अनुबंध पर हस्ताक्षर जो दोनों देशों के निजी रक्षा उद्योगों के बीच अधिक सहयोग की अनुमति देगा।

एक नया '2+2' विदेश और रक्षा मंत्रियों का संवाद।

द्विपक्षीय रणनीतिक ऊर्जा साझेदारी अप्रैल 2018 में शुरू की गई थी जिसके तहत भारत ने अमेरिका से कच्चे तेल और एलएनजी का आयात करना शुरू कर दिया है। अब, अमेरिका कच्चे तेल के आयात और हाइड्रोकार्बन का भारत का छठा सबसे बड़ा स्रोत है।पहले भारत-अमेरिका त्रि-सेवा सैन्य अभ्यास का उद्घाटन और मौजूदा सैन्य अभ्यासों का विस्तार।यूएस मैरीटाइम सिक्योरिटी इनिशिएटिव में भारत और दक्षिण एशिया को शामिल करना।[15,16]

इन गहन संबंधों ने आतंकवाद के खिलाफ अमेरिका से मजबूत समर्थन हासिल करने में मदद की है।यह पुलवामा हमले के बाद स्पष्ट हो गया, जिसके कारण संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 1267 के तहत जैश-ए-मोहम्मद के प्रमुख मसूद अजहर को वैश्विक आतंकवादी के रूप में नामित किया गया।साथ ही, पाकिस्तान को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे-लिस्ट में रखना।अमेरिका अपनी एशिया नीति के तहत चीन के आक्रामक उदय को रोकने के लिए भारत को एक आदर्श संतुलनकर्ता के रूप में देखता है। इसलिए, अमेरिका ने दक्षिण चीन सागर और हिंद महासागर में चीन का मुकाबला करने के लिए इंडो-पैसिफिक की अवधारणा तैयार की है।

क्वाड की अवधारणा द्वारा अमेरिका ने भारत को इंडो-पैसिफिक कथा के एक अभिन्न अंग के रूप में नामित किया है ।[17,18]

आगे का रास्ता

ऐतिहासिक परमाणु समझौते (2008) के बावजूद, असैन्य परमाणु सहयोग आगे नहीं बढ़ा है, लेकिन वेस्टिंगहाउस के साथ छह परमाणु रिएक्टर बनाने का समझौता अंततः भारतीय धरती पर अमेरिकी परमाणु ऊर्जा लाएगा।

समुद्री क्षेत्र में चीन का मुकाबला करने के लिए, भारत को नेविगेशन की स्वतंत्रता और नियम-आधारित व्यवस्था को संरक्षित करने के लिए, भारत-प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका और अन्य भागीदारों के साथ पूरी तरह से जुड़ने की आवश्यकता है।[19,20]

अंतरराष्ट्रीय राजनीति में न कोई स्थायी मित्र होता है और न ही कोई स्थायी दुश्मन, ऐसे परिदृश्य में केवल स्थायी हित होते हैं, भारत को अपनी रणनीतिक हेजिंग की विदेश नीति को जारी रखना चाहिए ।

21वीं सदी में विश्व व्यवस्था को आकार देने के लिए भारत-अमेरिका संबंध महत्वपूर्ण हैं। संबंधों की पूरी क्षमता का एहसास करने के लिए, दोनों सरकारों को अब अधूरे समझौतों को पूरा करने का प्रयास करना चाहिए और व्यापक रणनीतिक वैश्विक साझेदारी के लिए पाठ्यक्रम निर्धारित करना चाहिए ।

| e-ISSN: 2319-8753, p-ISSN: 2347-6710| www.ijirset.com | Impact Factor: 7.569|

|| Volume 10, Issue 12, December 2021 ||

| DOI:10.15680/IJIRSET.2021.1012175 |

## परिणाम

एक ठेठ बॉलीवुड नाटक की तरह, अंत भला तो सब भला। फिर भी, यह पूछना अनिवार्य है: ये दो प्रसंग हमें भारत-अमेरिका संबंधों की सीमा और सीमाओं के बारे में क्या बताते हैं? क्या भारत-अमेरिका साझेदारी शॉक-प्रूफ है, या यह अभी भी अस्थिर आधार पर आधारित है, और भारत-प्रशांत भू-राजनीति पर व्यापक अभिसरण के बावजूद नाटकीय बदलाव की संभावना है? [21,22]

जैसा कि बिडेन प्रेसीडेंसी अमेरिका के मध्यम वर्ग के लिए एक विदेश नीति पेश करती है, जिसका आधार अमेरिकी अर्थव्यवस्था की स्वस्थता को बहाल करना है, यह ट्रम्प के "अमेरिका फर्स्ट" के आह्वान से कितना अलग हो सकता है? हाल के इतिहास में किसी भी बिंदु की तुलना में अमेरिकी विदेश नीति की रूपरेखा इसकी घरेलू अनिवार्यताओं से अधिक मजबूती से जुड़ी हुई है। ट्रम्प के "अमेरिका फर्स्ट" मंत्र से बिडेन के "रिस्टोरिंग अमेरिका" की ओर बढ़ने वाले प्रवाह और वाशिंगटन के बाकी दुनिया के साथ जुड़ने के तरीके पर इसका प्रभाव, भारत सहित कई देशों के राजनयिक नेविगेशन कौशल का परीक्षण करेगा।

भारत-प्रशांत के बारे में वाशिंगटन के रणनीतिक दृष्टिकोण में भारत को दी गई प्राथमिकता मजबूत बनी हुई है। एच igh स्तरीय यात्राओं और आभासी कॉल दोनों के बीच कैसे वाशिंगटन नई दिल्ली के साथ अपने सामरिक भागीदारी के लिए पाठ्यक्रम चार्ट करने का इरादा रखता के स्वर निर्धारित किया है। रक्षा और सुरक्षा सहयोग, जिसने साझेदारी का मूल आधार बनाया है, वह उसी तरह भाप इकट्ठा करना जारी रखेगा जैसे उसने ट्रम्प प्रशासन के दौरान किया था। "2 + 2" संवाद रक्षा और दोनों देशों के विदेश मंत्रालयों के बीच, मूलभूत समझौतों पर हस्ताक्षर , और कई संयुक्त कार्य समूहों रक्षा सहयोग ढांचे के तहत इस बढ़ती भागीदारी के ठोस विशेषताएं हैं। [23]

विज्ञापन
बाइडेन प्रशासन के तहत, भारत-अमेरिका साझेदारी शायद अधिक बहुआयामी चरित्र का प्रदर्शन करेगी। हालांकि इसका मतलब सहयोग के लिए अधिक अवसर हो सकता है, यह एक अधिक जटिल नीति निर्माण वातावरण की भी भविष्यवाणी कर सकता है, जिसके लिए नई दिल्ली को वाशिंगटन से निपटने में अपने हितों की रक्षा और बढ़ावा देने के मामले में अधिक कुशल होने की आवश्यकता है। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एक हरित अर्थव्यवस्था के निर्माण के इरादे से भारत सरकार किस तरह से परिणाम-आधारित साझेदारी बना सकती है, यह भारतीय कूटनीति और राजनीतिक नेतृत्व के लिए एक चुनौतीपूर्ण कार्य रहेगा। के माध्यम से भारत-अमेरिका जलवायु और स्वच्छ ऊर्जा एजेंडा 2030 भागीदारी, दोनों ने 2030 के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किए हैं। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे, प्रौद्योगिकियों और संस्थानों में संशोधन करने में अधिक समन्वय को उत्प्रेरित करने के लिए दोनों देश किस हद तक रुचि और रणनीतियों को संरेखित करने में सक्षम होंगे, यह देखा जाना बाकी है।

| e-ISSN: 2319-8753, p-ISSN: 2347-6710| www.ijirset.com | Impact Factor: 7.569|

|| Volume 10, Issue 12, December 2021 ||

| DOI:10.15680/IJIRSET.2021.1012175 |

जबकि ट्रम्प प्रशासन ने इंडो-पैसिफिक में भारत-अमेरिका साझेदारी की रक्षा और सुरक्षा नींव के लिए मजबूत प्रतिबद्धता दिखाई, आर्थिक संबंध पीछे रह गए, ट्रम्प ने टैरिफ पारस्परिकता और व्यापार संतुलन के लिए एक सख्त लेन-देन के दृष्टिकोण को प्राथमिकता दी, और फोकस खो दिया। दोनों देशों के बीच घनिष्ठ आर्थिक संबंधों की रणनीतिक अनिवार्यता। ट्रम्प युग भारत-अमेरिका आर्थिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए एक परिवर्तनकारी समझौता करने में विफल रहा। मिनी-ट्रेड सौदे पर व्यापक रूप से अपेक्षित हस्ताक्षर बाजार पहुंच और बौद्धिक संपदा संकटों पर लंबित मुद्दों को हल करने के लिए दोनों सिरों पर काम के बावजूद गिर गया। टैरिफ पर दरार सबसे अधिक संभावना एक बिडेन प्रेसीडेंसी की बातचीत फिर से शुरू करने और बकाया व्यापार मुद्दों को हल करने की उम्मीदों पर टिकी होगी।[23,24]

**US vaccine donation**

बिडेन प्रशासन एक अमेरिकी विदेश और घरेलू नीति बनाने पर आमादा है जो अमेरिकी मध्यम वर्ग को पूरा करता है, बुनियादी ढांचे को बहाल करता है, अफगानिस्तान में दो दशक के युद्ध से सैनिकों को वापस लाता है, अमेरिकी हितों के खिलाफ चीनी और रूसी कदमों को पीछे धकेलता है, और रोजगार पैदा करता है - सभी एक हरित अर्थव्यवस्था की महत्वाकांक्षी मांगों को पूरा करते हुए।

| e-ISSN: 2319-8753, p-ISSN: 2347-6710| www.ijirset.com | Impact Factor: 7.569|

|| Volume 10, Issue 12, December 2021 ||

| DOI:10.15680/IJIRSET.2021.1012175 |

इसलिए, नई दिल्ली में नीतिगत नेताओं को उन घरेलू और विदेशी अनिवार्यताओं को समझने और उनसे निपटने के तरीकों के बारे में सोचना होगा जो वाशिंगटन में नीति निर्माण को आकार देंगे।[25,26]

चुनौतियां सहयोग के अवसर पैदा कर सकती हैं। जिस तरह चीन की चुनौती ने भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक अदृश्य रणनीतिक अभिसरण बनाया और एक बढ़ते रक्षा और सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा दिया, व्यापार और अर्थशास्त्र, स्वास्थ्य सुरक्षा के क्षेत्र में बाधाएं और जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने से सहयोग के नए रास्ते बन सकते हैं। व्यावहारिकता और भावना का संतुलन हाल ही में पुलों का पुनर्निर्माण करता है, इससे पहले कि इतिहास का खराब स्वाद सामने आए, और फिर भी पिछले दावों की गूँज पैदा करता है कि अमेरिका एक अविश्वसनीय भागीदार है। अंतिम विश्लेषण में, यह नई दिल्ली पर निर्भर करेगा कि वह बिडेन के अमेरिका में व्यापक परिवर्तन की हवाओं को महसूस करे और दो जटिल लोकतंत्रों के बीच संबंधों को कुशलता से नेविगेट करे। [27]

## निष्कर्ष

पिछले हफ्ते, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता, या क्वाड के पहले व्यक्तिगत शिखर सम्मेलन के लिए व्हाइट हाउस में ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान के नेताओं की मेजबानी की। चारों नेताओं ने पहले की तरह अलग-अलग बयान देने के बजाय एक महत्वाकांक्षी संयुक्त बयान जारी किया । एजेंडा बड़े पैमाने पर जलवायु परिवर्तन और टीकों तक पहुंच जैसी वैश्विक चुनौतियों को हल करने पर केंद्रित था, यह दर्शाता है कि क्वाड केवल एक भू-राजनीतिक समूह नहीं है, जैसा कि चीन ने जोर दिया है।

फिर भी, भू-राजनीति महत्वपूर्ण बनी हुई है क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका एशिया में विदेश-नीति में बदलाव करता है। छह महीने से भी कम समय में, क्वाड " समान विचारधारा वाले भागीदारों का एक लचीला समूह " बन गया है , जैसा कि चार नेताओं ने मार्च में लिखा था, ताइवान स्ट्रेट में शांति और सुरक्षा जैसे मुद्दों को साहसपूर्वक अपने प्रेषण में शामिल करने के लिए। पिछले हफ्ते का शिखर सम्मेलन भी अफगानिस्तान से अमेरिका की वापसी की छाया में हुआ, जिसने वाशिंगटन के प्रति यूरोप के आशावाद को कम कर दिया है ।

पिछले हफ्ते क्वाड समिट से पहले बिडेन ने भारतीय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। भारत विशिष्ट रूप से उस पश्चिमी भाग के बीच स्थित है जहाँ से संयुक्त राज्य अमेरिका पीछे हटता हुआ प्रतीत होता है और दक्षिण-पूर्वी भाग जहाँ वह नए वादे कर रहा है। यूरोप में सहयोगियों के विपरीत, वाशिंगटन के इन मिश्रित संकेतों ने अभी तक नई दिल्ली की विश्वसनीयता को प्रभावित नहीं किया है।[28,29]

यूएस-भारत संबंध क्वाड का लिटमस टेस्ट हो सकता है। समूह ने हाल ही में तीन प्रमुख चुनौतियों को हल करने के लिए एक बाध्यकारी गोंद के रूप में लोकतांत्रिक आदर्शों का आह्वान किया है , जैसा कि इसके कार्य समूहों द्वारा परिलक्षित होता है: COVID-19 वैक्सीन वितरण, जलवायु परिवर्तन और उभरती प्रौद्योगिकियां। भारत को प्रत्येक क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है, लेकिन इसके संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ कई अनसुलझे मतभेद भी हैं, जैसे कि उनकी वैक्सीन आपूर्ति श्रृंखला के मुद्दे, जलवायु नीति के दृष्टिकोण और ताइवान और पाकिस्तान के संबंध में परस्पर विरोधी प्राथमिकताएं।

लंबे समय से दुनिया की फार्मेसी के रूप में जाना जाता है, भारत का हस्ताक्षर वैश्विक वैक्सीन वितरण कार्यक्रम मई में अपनी विनाशकारी COVID-19 लहर के दौरान अचानक रुक गया था, और इसका निर्माण टीके बनाने के लिए आवश्यक कच्चे माल पर अमेरिकी प्रतिबंधों से प्रभावित हुआ था । बिडेन प्रशासन भी शुरू में COVID-19 टीकों के लिए पेटेंट छूट का समर्थन करने से हिचकिचा रहा था , जिसका भारत ने समर्थन किया, हालांकि व्हाइट हाउस ने अंततः मना कर दिया। यदि विश्व व्यापार संगठन मंत्रिस्तरीय सम्मेलन नवंबर में प्रस्ताव को मंजूरी देता है, तो यह क्वाड के 1.2 बिलियन टीकों को दान करने और विश्व स्वास्थ्य संगठन के नेतृत्व वाली COVAX टीकाकरण पहल का समर्थन करने के लक्ष्य को बढ़ावा देगा ।[30,31]

अब जबकि इसने घर पर 800 मिलियन से अधिक शॉट्स प्रशासित किए हैं, भारत अक्टूबर में वैक्सीन निर्यात फिर से शुरू करने की योजना बना रहा है , उन्हें COVAX के माध्यम से आपूर्ति करेगा। जैसा कि भारत अपने वैश्विक आपूर्ति अभियान के लिए तैयार है, संयुक्त राज्य अमेरिका को भारतीय निर्माताओं को आवश्यक कच्चे माल की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करनी चाहिए।

| e-ISSN: 2319-8753, p-ISSN: 2347-6710| www.ijirset.com | Impact Factor: 7.569|

|| Volume 10, Issue 12, December 2021 ||

| DOI:10.15680/IJIRSET.2021.1012175 |

**Vaccines from America**

इस बीच, जलवायु परिवर्तन पर भारत का रिकॉर्ड संयुक्त रूप से अपने तीनों क्वाड पार्टनर्स से बेहतर है: भारत पेरिस समझौते के उत्सर्जन में कमी के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए ट्रैक पर एकमात्र जी -20 अर्थव्यवस्था है । हालांकि, अमेरिकी नीति निर्माताओं ने भारत को, जो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जक है , एक शुद्ध-शून्य प्रतिज्ञा करने के लिए प्रेरित किया है , एक दीर्घकालिक योजना जिसे भारतीय राजनेताओं ने तत्काल उपायों के बिना " पाई इन द स्काई " कहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका में ट्रम्प प्रशासन के दौरान सामरिक सहयोग लगभग स्थिर हो गया।

यदि बाइडेन प्रशासन अपने पूर्ववर्ती बराक ओबामा के तहत देखे गए संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के बीच जलवायु परिवर्तन शमन के लिए उत्साह को पुनर्जीवित करना चाहता है , तो उसे अक्षय और असैनिक परमाणु ऊर्जा, स्वच्छ ऊर्जा वित्त, ऊर्जा-कुशल प्रौद्योगिकी, क्षमता निर्माण के लिए रणनीति तैयार करनी चाहिए। और जलवायु लचीलापन पहल।[32]

**भविष्य का दायरा**

पिछले हफ्ते, क्वाड सदस्यों ने तकनीकी विकास के लिए मार्गदर्शक सिद्धांतों का अनावरण किया , और वे चीन पर सेमीकंडक्टर चिप निर्भरता को कम करने के इच्छुक हैं। भारत के पास स्वदेशी फाउंड्री नहीं है, लेकिन वह ताइवान की संभावित मदद से खुद को चिप्स की वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में शामिल करने के लिए बेताब है । अब स्मार्टफोन निर्माण में दूसरा सबसे बड़ा खिलाड़ी , भारत ने हालिया आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों से लाभ उठाने की भूख दिखाई है। यह वहां दुकान स्थापित करने वाली प्रत्येक कंपनी को 1 अरब डॉलर से अधिक का पुरस्कार देकर निर्माताओं को प्रोत्साहित करने को तैयार है ।

जैसा कि संयुक्त राज्य अमेरिका का लक्ष्य चिप निर्माण में वर्चस्व हासिल करना है और भारत बाजार में प्रवेश करने की कोशिश करता है, दोनों देशों के वाणिज्यिक खिलाड़ी अनिवार्य रूप से एक ही पाई के शेयरों के लिए होड़ करेंगे। अमेरिकी सरकार को उन नीतियों से बचना चाहिए जो सड़क पर उसके साथी को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती हैं। भारत के प्रयासों को मजबूत करने के लिए कुछ संयम बरतना और यहां तक कि इलेक्ट्रॉनिक्स में अपनी स्केलेबल मानव प्रतिभा से लाभ उठाना एक जीत की रणनीति होगी।

लंबी अवधि में, क्वाड का अघोषित मकसद आर्थिक और सैन्य दोनों तरह से चीन के उदय को संबोधित करना है। हालांकि समूह के नेताओं ने "एशियाई नाटो" लेबल का विरोध किया है, क्वाड मीटिंग नोट्स में ताइवान का उल्लेख इस अंतर्निहित मकसद को बढ़ाता है। इस संदर्भ में, संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत में भी महत्वपूर्ण मतभेद हैं। कुछ पर्यवेक्षक नई दिल्ली को अपनी सैन्य क्षमताओं और दक्षिण चीन सागर या ताइवान जलडमरूमध्य में बीजिंग का सामना करने की अव्यक्त प्रतिबद्धता दोनों के लिए एक कमजोर कड़ी के रूप में देखते हैं ।

चीन के उदय का मुकाबला करना निस्संदेह एक साझा लक्ष्य है, लेकिन भारत वर्तमान में ताइवान में शांति को दूर की कौड़ी मानता है।[33]

चीन के उदय का मुकाबला करना निस्संदेह एक साझा लक्ष्य है, लेकिन भारत वर्तमान में ताइवान में शांति को दूर की कौड़ी मानता है। नई दिल्ली की प्राथमिकताएं अपनी सीमाओं को सुरक्षित करते हुए अपने आर्थिक विकास को तेज करना है। कुछ विश्लेषकों ने तर्क दिया है कि भारत की कथित द्विपक्षीयता को भारत के लिए अमेरिकी समर्थन को कम करना चाहिए , इसकी जगह इंडोनेशिया या

| e-ISSN: 2319-8753, p-ISSN: 2347-6710| www.ijirset.com | Impact Factor: 7.569|

|| Volume 10, Issue 12, December 2021 ||

| DOI:10.15680/IJIRSET.2021.1012175 |

वियतनाम के साथ सहयोग करना चाहिए । लेकिन उन देशों ने यह संकेत नहीं दिया है कि वे बीजिंग के खिलाफ वाशिंगटन का पक्ष लेंगे। भले ही भारत ताइवान के साथ अपने राजनीतिक और आर्थिक संबंधों का विस्तार करता है, लेकिन इसका स्पष्ट सैन्य समर्थन स्वचालित नहीं होगा । भारत का आगे का रणनीतिक झुकाव चीनी जुझारूपन- और नई दिल्ली के प्रति अमेरिका की सहनशीलता पर निर्भर करता है।

अमेरिकी सांसदों के लिए एक और कांटेदार मुद्दा हथियारों के लिए रूस पर भारत की निरंतर निर्भरता है। रूसी इन्वेंट्री क्वाड देशों की संयुक्त रूप से संचालित करने की क्षमताओं को बाधित कर सकती है। नई दिल्ली द्वारा मॉस्को की एस-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली की खरीद पर प्रतिबंधों का खतरा मंडरा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य जमीन पर चीनी सैल्वो को रोकना है। लेकिन जैसा कि यूएस सेन टॉड यंग ने तर्क दिया है, प्रतिबंध क्वाड एजेंडा को पटरी से उतार सकते हैं , खासकर संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके सहयोगियों से भारत की बढ़ती हथियारों की खरीद के मद्देनजर । जैसा कि क्वाड अपने समुद्री गठबंधन को मजबूत करना चाहता है, संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए रूसी प्लेटफॉर्म के आयात को एक घर्षण बिंदु बनाने के बजाय इसे अनदेखा करना बुद्धिमानी होगी।

भारत इसी तरह पाकिस्तान के अमेरिकी आवास को लेकर चिंतित है। अफगानिस्तान की हार में पाकिस्तानी सेना की भूमिका और यहां तक कि प्रतिबंधों की मांग पर वाशिंगटन में आम सहमति के बावजूद , पाकिस्तान की स्थिति अभी भी इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए, विशेष रूप से आतंकवाद के लिए मूल्यवान बना सकती है। लेकिन भारत संयुक्त राज्य अमेरिका को भारत विरोधी आतंकवादी समूहों के लिए पाकिस्तान के समर्थन की अनदेखी करने के रूप में देखता है, जबकि उसे सहायता के साथ पुरस्कृत करता है। अफ़ग़ानिस्तान से पीछे हटने से भारत के भारत विरोधी जिहाद के लिए पाकिस्तान के समर्थन के बारे में भारत की आशंका और बढ़ जाती है - जिस तरह से उसने तालिबान का समर्थन किया।

पाकिस्तान भारत के लिए लगातार खतरा बना रहा है, और नई दिल्ली को उम्मीद है कि वह अपने दम पर सैन्य रूप से इससे निपटेगा। हालांकि, जितना अधिक यह अपने पश्चिमी मोर्चे पर कब्जा रखता है, उतना ही कम भारत अपने पूर्वी और समुद्री मोर्चों पर ध्यान केंद्रित कर सकता है, जहां क्वाड एक साझा खतरा देखता है। लेकिन नई दिल्ली की क्षमताओं का ऐसा आकलन शायद ही कभी वाशिंगटन की नीतिगत सोच में शामिल होता है, जो अफगानिस्तान-पाकिस्तान सीमा पर आवश्यकताओं के आधार पर सीमित है।

यह सब नई दिल्ली के लिए क्वाड के भीतर एक प्रश्न उठाता है: यदि पाकिस्तान के प्रति अमेरिकी नीति भारत की चिंताओं पर विचार किए बिना अपनी संकीर्ण रसद जरूरतों से निर्धारित होती है, तो भारत को बिना किसी अपेक्षित लाभ के ताइवान के लिए खुद को कितना बढ़ाना चाहिए? अमेरिका-भारत संयुक्त बयान पिछले सप्ताह परोक्ष रूप से सीमा पार से आतंकवाद की समस्या का पता में किसी भी पिछले एक की तुलना में bolder था, लेकिन समय है कि क्या अमेरिका के प्रयासों unremittingly पाकिस्तान की ओर क्षमा रूप में अपनी छवि को संबोधित करने के लिए पर्याप्त हैं बता देंगे।[34]

संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के बीच राजनीतिक मतभेदों के लिए संवेदनशील प्रबंधन और धैर्यवान, व्यावहारिक समाधानों की आवश्यकता होती है जो क्वाड के व्यापक लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए आपसी चिंताओं को दूर करते हैं। दोनों देशों के बीच रचनात्मक और अनुकूल कूटनीति भविष्य की किसी भी क्वाड सफलता को आधार बनाएगी - एक ऐसा परीक्षण जो न तो विफल हो सकता है।[34]

## संदर्भ


1. ^ "भारत, अमेरिका और एकजुटता का एक वर्ष" . इंडियन एक्सप्रेस। 26 दिसंबर 2015 । 30 दिसंबर 2015 को लिया गया ।
2. ^ "भारत ने दक्षिण चीन सागर में अमेरिका के साथ संयुक्त नौसेना गश्ती को खारिज कर दिया" । अमेरिका की आवाज। 11 मार्च से 2016 संग्रहीत मूल 11 मार्च, 2016 को।
3. ^ "भारत-अमेरिका सहयोग के कारण कई आतंकी साजिश नाकाम: व्हाइट हाउस" । द हिंदू । 8 जनवरी 2017 । पुन: प्राप्त 12 जनवरी, 2017 ।
4. ^ "भारत-अमेरिका ने मिलकर 'कई आतंकवादी साजिशों को विफल किया', शीर्ष अमेरिकी अधिकारी कहते हैं" . एनडीटीवी डॉट कॉम । पुन: प्राप्त 12 जनवरी, 2017 ।
5. ^ ग्रिफिथ्स, जेम्स. "चीन के साथ हिमालय गतिरोध के बाद भारत ने अमेरिका के साथ रक्षात्मक समझौते पर हस्ताक्षर किए" । सीएनएन । से संग्रहीत मूल 28 अक्टूबर, 2020 पर । 27 अक्टूबर, 2020 को लिया गया ।
6. ^ [1] संग्रहीत मई 4, 2012, पर वेबैक मशीन
7. ^ शेफ़र, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका (2010) पीपी 89-117
8. ^ "अमेरिका और भारत छह परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं" । रॉयटर्स । 13 मार्च 2019 । 28 मार्च 2019 को लिया गया ।
9. ^ हवाई में अमेरिकी सेना के साथ भारतीय सैनिकों का प्रशिक्षण , signonsandiego.com

| e-ISSN: 2319-8753, p-ISSN: 2347-6710| www.ijirset.com | Impact Factor: 7.569|

|| Volume 10, Issue 12, December 2021 ||

| DOI:10.15680/IJIRSET.2021.1012175 |


10. ^ वायु सेना कर्मियों भारतीय वायु सेना के साथ उड़ान भरने संग्रहीत पर 16 दिसंबर 2008 वेबैक मशीन , pacaf.af.mil
11. ^ भारतीय सैनिकों के साथ अमेरिकी मरीन, नाविकों , Navy.mil
12. ^ पीटीआई, ललित के। झा (4 अगस्त, 2018)। "अमेरिका से STA-1 का दर्जा पाने वाला भारत तीसरा एशियाई देश" । लाइवमिंट । 5 दिसंबर, 2018 को लिया गया । [ स्थायी मृत लिंक ]
13. ^ "अमेरिका: भारत सभी शर्तों को पूरा करता है, लेकिन चीन के वीटो के कारण परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह से बाहर - टाइम्स ऑफ इंडिया" । टाइम्स ऑफ इंडिया । 5 दिसंबर, 2018 को लिया गया ।
14. ^ "शीर्ष भारत आयात भागीदार" । Worldsrichestcountries.com । 30 दिसंबर 2015 को लिया गया ।
15. ^ "विदेश व्यापार: डेटा" ।
16. ^ "भारत - अमेरिकी व्यापार और आर्थिक संबंध" । से संग्रहीत मूल 12 मई, 2008 को । 20 मई 2008 को लिया गया ।
17. ^ **ए बी** "इंडिया" । अमेरिकी विदेश विभाग । 2 अप्रैल 2016 को लिया गया ।
18. ^ "टॉप इंडिया एक्सपोर्ट्स" । Worldsrichestcountries.com । 7 अप्रैल 2016 को लिया गया ।
19. ^ "शीर्ष अमेरिकी आयात" । Worldsrichestcountries.com । 7 अप्रैल 2016 को लिया गया ।
20. ^ "शीर्ष अमेरिकी निर्यात" । Worldsrichestcountries.com । 7 अप्रैल 2016 को लिया गया ।
21. ^ "शीर्ष भारत आयात" । Worldsrichestcountries.com । 7 अप्रैल 2016 को लिया गया ।
22. ^ "द यूएस एंड इंडिया: एन इमर्जिंग एंटेंटे?" . 2001-2009.state.gov । पुन: प्राप्त 27 जुलाई, 2017 ।
23. ^ द इंडियन हॉक, डिफेंस न्यूज (27 अक्टूबर, 2020)। "27 अक्टूबर 2020" । द इंडियन हॉक । 27 अक्टूबर, 2020 को लिया गया ।
24. ^ **ए बी** "द असम ट्रिब्यून ऑनलाइन" । संग्रह.इस . 16 जून, 2007 से संग्रहीत मूल 16 जून, 2007 को।
25. ^ अमेरिका और भारत: दुनिया के सबसे पुराने और सबसे बड़ा लोकतंत्र शेयर ऐतिहासिक संबंध संग्रहीत 1 अप्रैल 2016 को वेबैक मशीन
26. ^ टीआई ट्रेड। "असम ट्रिब्यून ऑनलाइन" । असमट्रिब्यून डॉट कॉम । 21 नवंबर 2009 को पुनःप्राप्त ।
27. ^ "ओबामा ने सुरक्षा परिषद में भारत के लिए स्थायी सीट का समर्थन किया" . सीएनएन । 8 नवंबर 2010।
28. ^ "2+2 संवाद: भारत, अमेरिका ने भू-स्थानिक खुफिया पर महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए" । इंडियन एक्सप्रेस । 27 अक्टूबर 2020 । 27 अक्टूबर, 2020 को लिया गया ।
29. ^ "2021 भारत-अमेरिका साझेदारी को व्यापक बनाने के लिए महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करना: बिस्वाल" । द इकोनॉमिक टाइम्स । 25 दिसंबर 2020।
30. ^ "रूस पर अमेरिकी प्रतिबंध भारत को नुकसान पहुंचा सकते हैं। कांग्रेस एक फिक्स पर कुश्ती कर रही है" । रक्षा समाचार । 18 जुलाई 2018।
31. ^ "व्हाई पनिशिंग इंडिया ऑन रशिया विल बी अ मिस्टेक फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स" . राजनयिक । 17 मई, 2018। मूल से 28 जून, 2019 को संग्रहीत ।
32. ^ "भारत, रूस के हथियारों के सौदों के लिए प्रतिबंधों का सामना कर रहा है, कहता है कि वह अमेरिका को खर्च करना चाहता है" । सीएनबीसी । मई 23, 2019। मूल से 28 जून , 2019 को संग्रहीत ।
33. ^ "अमेरिकी सीनेटरों ने बिडेन से रूसी सौदे पर भारत के प्रतिबंधों से बचने का आग्रह किया" . रॉयटर्स । 27 अक्टूबर 2021।
34. ^ "भारत के हथियार रूस के साथ सौदे क्यों बाइडेन के लिए सिरदर्द बनने वाले हैं" . पौलिटिको । 1 अक्टूबर 2021।

INNO SPACE

SJIF Scientific Journal Impact Factor

**Impact Factor:**
**7.569**

crossref

INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER INDIA

निस्केयर NISCAIR

# INTERNATIONAL JOURNAL OF INNOVATIVE RESEARCH

## IN SCIENCE | ENGINEERING | TECHNOLOGY

9940 572 462 6381 907 438 ijirset@gmail.com

Scan to save the contact details

www.ijirset.com